मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सिंगापुर को आमंत्रित किया

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान को अगले 5 वर्षों में 180 बिलियन से दोगुना करके 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन के अनुसार हम भी विकसित राजस्थान-2047 के लिए काम कर रहे हैं और सिंगापुर इसमें हमारा बहुत महत्वपूर्ण साझेदार बन सकता है। शर्मा बुधवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सिंगापुर से आए प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजस्थान की 'अतिथि देवो भव:' की संस्कृति रही है तथा राजस्थान अपने अद्वितीय संस्कृति और विरासत के लिए दुनियाभर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का सिंगापुर बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है तथा सिंगापुर ने अपने आर्थिक मॉडल से विश्व को प्रेरित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य, जल संचय, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हो रहा है। राज्य के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमनें कुल बजट का 8.26 फीसदी बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया है। वहीं, कैच द रैन तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के माध्यम से राज्य में जल संचय को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में पेयजल एवं सिंचाई के लिए हमने ईआरसीपी का ऐतिहासिक एमओयू किया है। साथ ही, इसे धरातल पर उतारने का काम भी शुरू हो चुका है।

शर्मा ने कहा कि राज्य में विश्वभर से निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए हम आगामी 9 से 11 दिसम्बर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस समिट के तहत अब तक 20 लाख करोड़ रूपए के एमओयू हो चुके हैं। शर्मा ने इस ऐतिहासिक आयोजन में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल को भी आने का न्यौता दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सिंगापुर डेलिगेशन की यह यात्रा न केवल राजस्थान और सिंगापुर के संबंधों को मजबूत बनाएगी बल्कि राजस्थान के विकास और वैश्विक संपर्क में नई संभावनाएं भी खोलेगी।

इस दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति, जल संचय, चिकित्सा एवं राइजिंग समिट से जुड़े कार्यक्रमों, नवाचारों तथा योजनाओं की जानकारी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि राजस्थान में नवीनकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कृषि सहित विभिन्न क्षेंत्रों में अपार संभावनाएं हैं तथा राजस्थान की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवा हैं। ऐसे में, राजस्थान विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राजस्थान में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इंटर लिंकिंग रिवर तथा ग्राउण्ड वॉटर रिर्चाज के बारे में जानकारी दी।

इस दौरान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री ए. राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से राज्य की लगभग 88 प्रतिशत जनसंख्या को नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जा रहा है। आयुक्त उद्योग रोहित गुप्ता ने बताया कि राजस्थान देश में रिन्यूबल एनर्जी, जेम्स एंड ज्वैलरी, टैक्सटाईल, माइन्स तथा पैट्रोकेमिकल्स में अग्रणी राज्य हैं। उन्होंने राइजिंग राजस्थान की रूप रेखा भी बैठक में रखी।

बैठक में सिंगापुर से आए प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है तथा स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऊर्जा के क्षेत्र में यहां बेहतरीन काम हो रहा है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेम चंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सिंगापुर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेम चंद बैरवा, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

- 'विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्य में सिंगापुर महत्वपूर्ण साझेदार'

प्रदेश में बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करना हमारी प्राथमिकता : दिया कुमारी

- प्रदेश के 158 निकायों में सड़कें बनायेगा पी.डब्लू.डी.
- 180 करोड़ की लागत से 270 किमी. की सड़कें बनेगी

जयपुर। 158 नगरीय निकायों में 270 किमी. सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाएगा। इसके लिए 158 निकायों में सड़क निर्माण के 728 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्रामीण सड़कों के साथ शहरी निकायों के सड़क नेटवर्क को विकसित कर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के मामले में देश में नम्बर वन बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा के तहत 295 नगरीय निकायों में 317.50 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई जानी है।

अजमेर जिले के नगरीय निकायों में 9 किमी सड़क निर्माण के 15 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, केकड़ी जिले में 2.8 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपये, ब्यावर जिले में 4.9 किमी सड़क के 9 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये,

भीलवाडा जिले में 7.4 किमी सड़क के 18 कार्यों के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपये, शाहपुरा जिले में 3.8 किमी सड़क के 5 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, डीडवाना- कुचामन जिले में 18.6 किमी सड़क के 40 कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये, करौली जिले में 6.8 किमी सड़क के 25 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये, बीकानेर में 8.5 किमी सड़क के 20 कार्यों के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपये, हनुमानगढ़ जिले में 6.2 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपये, अनूपगढ़ जिले में 3.8 किमी सड़क के 10 कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये, श्रीगंगानगर जिले में 16.1 किमी सड़क के 38 कार्यों के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपये, चुरू जिले में 19.4 किमी सड़क के 46 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपये, दूदू जिले में 2.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, कोटपुतली बहरोड़ जिले में 19.1 किमी सड़क के 80 कार्यों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपये, खैरथल तिजारा जिले में 13.1 किमी सड़क के 37 कार्यों के लिए 9 करोड़ 40 लाख रुपये, सीकर जिले में 16.5 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपये, फलोदी जिले में 4.9 किमी सड़क के 2 कार्यों के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये, पाली जिले में 24.7 किमी सड़क के 58 कार्यों के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपये, सिरोही जिले में 11.1 किमी सड़क के 29 कार्यों के लिए 7 करोड रुपये, बाडमेर जिले में 5.5 किमी सड़क के 8 कार्यों के लिए 3 करोड रुपये, बूंदी जिले में 7.4 किमी सड़क के 17 कार्यों के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपये, बारां जिले में 8.1 किमी सड़क के 39 कार्यों के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये, झालाबाड़ जिले में 4.3 किमी सड़क के 15 कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये, सवाई माधोपुर जिले में 7.7 किमी सड़क के 27 कार्यों के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपये, उदयपुर जिले में 7.6 किमी सड़क के 12 कार्यों के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये, चितौडगढ़ जिले में 12.2 किमी सड़क के 41 कार्यों के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपये, राजसमन्द जिले में 12.5 किमी सड़क के 31 कार्यों के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपये, बांसवाडा जिले में 6.2 किमी सड़क के 21 कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपये तथा प्रतापगढ़ जिले के नगरीय निकायों में 7.3 किमी सड़क के 13 कार्यों के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

सरपंचों और पंचों ने देखी विधानसभा

जयपुर। राजस्थान की विभिन्न ग्राम पचांयतो के सरपंचों, पंचो, जिला परिषद सदस्यों और समाज सेवियों ने राजस्थान विधान सभा को देखा। विधान सभा में स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में राजस्थान के राजनैतिक आख्यानों का जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन किया।

राजस्थान विधान सभा में जन-दर्शन कार्यक्रम के तहत विधान सभा का अवलोकन करने आये ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी का संदेश पढ़कर सुनाया गया।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में सिंगापुर डेलीगेशन का स्वागत किया

जयपुर। विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी भाजपा की रीति और नीति को समझने के लिए सिंगापुर डेलीगेशन बुधवार को भाजपा कार्यालय पहुंचा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ अरूण चतुर्वेदी, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, भाजपा पदाधिकारियों ने राजस्थानी परम्परा के अनुसार तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर कार्यालय में सिंगापुर डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि सिंगापुर डेलीगेशन ने विश्व की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी भाजपा की संगठनात्मक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं को संगठन द्वारा आमजन तक पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाता है, इस पर चर्चा की गई। भाजपा की सबसे छोटी ईकाई बूथ समिति से लेकर प्रदेश स्तरीय संरचना पर सिंगापुर डेलीगेशन के साथ चर्चा की गई।

भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ अरूण चतुर्वेदी ने बताया कि सिंगापुर डेलीगेशन ने भाजपा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा की। इस दौरान डेलीगेशन को बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए है। भाजपा ने राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष रूप महिला मोर्चा का गठन किया तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने ही पार्टी संविधान में 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। इसके साथ ही भाजपा ने ही पंचायती राज चुनावों में महिलाओं के आरक्षण को 50 फीसदी करने का ऐतिहासिक कार्य किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी विभिन्न योजनाओं को शुरू किया।

भाजपा जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सिंगापुर से 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भाजपा कार्यालय में संगठन और सत्ता के बीच अध्ययन के लिए आया है। इसमें सिंगापुर सरकार के मंत्री जेनिल पुथुचेरी, डेसमंड टैन कोक मेंग, गेन सियो हुआंग, संसदीय सचिव शॉन हुआंग, संसद सदस्य जी याओ क्वान, राचेल ओंग, सक्तियांदी सुपाट भाजपा कार्यालय पहुंचे। इनके साथ सिंगापुर सत्तारूढ पार्टी कैडर के लियोनार्ड चिउ, थिरू, जेसन सलीम, जेनिका एनजी, जयदेव उन्नीथन के साथ डैनी नगियम, लिंडा एन जी, जैसलिन ओंग और अल्लाह थाम भी साथ में थे।

सफाईकर्मी भर्ती प्रकरण की सुनवाई करेगी खंडपीठ

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सफाई कर्मचारी भर्ती-2024 के नए विज्ञापन व भर्ती नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए खंडपीठ में भेज दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सियाराम माली व अन्य की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि मामला भर्ती नियमों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मामले की सुनवाई खंडपीठ में होनी चाहिए।

पूर्व सरपंच हत्याकांड में आरोपियों की जमानत रद्द

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने नीमराणा के सिलापुर गांव के पूर्व सरपंच दिनेश कुमार की गोली मारकर हत्या करने से जुड़े मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों सत्यप्रकाश, अभिमन्यु और जयवीर को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आदेश मृतक के भाई की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और आरोप पत्र में पेश साक्ष्यों को देखे बिना अपराध होने के एक साल के भीतर आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।

भर्तियों के मुद्दों के निस्तारण के लिए क्यों न अलग से बने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों में अभ्यर्थियों के अलग-अलग तथ्यात्मक मुद्दों के निस्तारण के लिए अलग से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाए जाने की मंशा जताई है। अदालत ने कहा कि क्यों न हाईकोर्ट में याचिका दायर करने से पहले इस प्रकोष्ठ में मामला पेश किया जाए और यहां अपीलीय अधिकारी स्तर पर मुद्दों को तय किया जाए। इसके बाद भी यदि अभ्यर्थी संतुष्ट न हो तो फिर हाईकोर्ट में याचिका पेश की जाए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भर्तियों से जुडे विभिन्न मुद्दों के निस्तारण के लिए कोई आयोग या कमेटी नहीं है। ऐसे में सीधे हाईकोर्ट आने से अदालत पर भी केसों का भार बढ रहा है। अदालत ने 22 नवंबर को प्रमुख चिकित्सा सचिव को भी इस संबंध में पक्ष रखने को कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश एएनएम भर्ती से जुडे विभिन्न मुद्दों पर दायर ज्योति कुमारी मीना व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।